उपलब्धता कृषि उत्पाद के विपणन, कृषि परिसंस्करण, उपभोक्ता मदों के संवितरण आदि के क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध एक सुदृढ़ आर्थिक शक्ति के रुप में इनका आविर्भाव हुआ है। अपने आकार एवं महत्व के बावजूद, सहकारी क्षेत्र कमजोर संगठनात्मक संरचना, सदस्यों की निष्क्रियता, संसाधनों के लिए सरकार पर बहुत अधिक निर्भरता, बढ़ते अतिदेय, व्यवसायीकरण की कमी जैसी कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है।

(ग) सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने एवं उनके पुनर्जीविकरण के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें निम्नांकित बातें शामिल हैं:—

— सहकारी समितियों को गुंजायमान राजनीतिक संगठन राजनीतिक संगठन बनाने हेतु एक मॉडल विधिक ढांचे का मसौदा बनाना; राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर संघीय सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना;

— सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों को सदस्यों द्वारा उनके आर्थिक एवं सामाजिक समुन्नित हेतु स्वामित्वधीन, प्रबंधित एवं नियंत्रित आत्म निर्भर, आधारभूत प्रजातांत्रिक संस्थानाओं के रूप में विकसित करना है।

— प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए व्यवसाय विकास योजनाओं की तैयारी एवं कार्यान्वयन द्वारा कृषि ऋण समीक्षा समिति की सिफारिशों का प्रचालन करना; एवं

— प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की जमा वृद्धि बढ़ाने के लिए मॉडल जमा गारंटी योजना की तैयारी।

Norms for Assistance to Flood Affected States

2849. SHRI H.. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the norms regarding assistance to the States affected by flood and drought; and

(b) the details of assistance state-wise for the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) and (b) Under the existing scheme of financing relief expenditure introduced from the financial years 1990-91, a Calamity Relief Fund (CRF) with an annual corpus of Rs. 804.00 crores has been constituted with a Central contribution of Rs. 603.00 crores and States' contribution of Rs. 201.00 crores. The state-wise allocation of annual CRF has been made on the recommendations of the IX Finance Commission. The State Governments are required to undertake relief measures in the wake of all natural calamities, using the corpus of the CRF. A statement containing state-wise annual allocation of CRF, Central share and the releases made during the years, 1990-91, 1991-92 and 1992-93 by Government of India, is enclosed.

STATEMENT

State	Annual Allocation in Calamity Relief Fund (CRF)	Central Share of CRF	Releases made by Govt. of India from Central share of CRF		
			1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6
Andhra Pradesh	86.00	64.50	125.66	49.21	36.9075
Arunachal Pradesh	2.00	1.50	1.50	1.50	1.1250
Assam	30.00	22.50	22.50	22.50	16.8750

(Rs. in crores)

1	2	3	4	5	6
Bihar	35.00	26.25	26.25	26.25	39.3750
Goa	1.00	0.75	0.75	0.75	0.5625
Gujarat	85.00	63.75	63.75	63.75	63.7500
Haryana	17.00	12.75	12.75	12.75	9.5625
Himachal Pradesh	18.00	13.50	13.50	13.50	10.1250
Jammu & Kashmir	12.00	9.00	9.00	9.00	13.5000
Karnataka	27.00	20.25	20.25	20.25	30.3750
Kerala	31.00	23.25	23.25	23.25	34.8750
Madhya Pradesh	37.00	27.75	27.75	27.75	27.7500
Maharashtra	44.00	33.00	33.00	33.00	33.0000
Manipur.	1.00	0.75	0.75	0.75	0.7500
Meghalaya	2.00	1.50	1.50	1.50	1.1250
Mizoram	1.00	0.75	0.75	0.75	0.7500
Nagaland	1.00	0.75	0.75	0.75	0.5625
Orissa	47.00	35.25	57.13	29.78	22.3350
Punjab	28.00	21.00	21.00	21.00	15.7500
Rajasthan	124.00	93.00	93.00	93.00	69.7500
Sikkim	3.00	2.25	2.25	2.25	1.6875
Tamil Nadu	39.00	29.25	29.25	29.25	43.8750
Tripura	3.00	2.25	2.25	2.25	2.2500
Uttar Pradesh	90.00	67.50	67.50	67.50	122.5800
West Bengal	40.00	30.00	30.00	30.00	22.5000
Total	804.00	603.00	686.04	582.24	621.6975

मानसून की वर्षा

2850. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि उत्पादन भूमि अधिकतर मानसून की वर्षा की अवधि पर ही आधारित रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में मानसून की वर्षा और अन्य वर्षा का होना प्रायः अनिश्चित ही होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस अनिश्चित वर्षा में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देकर खाद्यान्नों का अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में मोटे अनाजों के उत्पादन के लिये सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या योजनायें कार्यान्वित करने का निश्चय किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) भूमि उपयोग सांख्यिकी 1988-89 (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार लगभग 68 प्रतिशत कृष्य भूमि वर्षा सिंचित है।

(ख) जी, हां। मानसून तथा समय-समय पर होने वाली अन्य प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा वितरण में कुछ जोखिम और अनिश्चितता तो होती ही है।

(ग) जी, हां।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 1996-97 के अंत तक देश में मोटे अनाज के उत्पादन का लक्ष्य 39.00 मिलियन मीटरी टन निर्धारित किया गया है। इस उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम मक्का और कदन्न का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके आठवीं योजनावधि के दौरान जारी रहने की संभावना है।

Increase in Agricultural Production

2851. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the P.M.'s reported remarks at the first agricultural science congress held in New Delhi on 12th November, 1992 emphasising the need for increase in agricultural production by three times in the next decade as published in the Hindustan Times dated 13th November, 1992 under the heading "Need to increase farm output";

(b) whether it is a fact that there is continuous decrease in the area under